(ग) थल सेनाध्यक्ष के पत्र पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू): (क) जी, नहीं।

(ख) रक्षा सेनाओं के लिए पांचवें वेतन आयोग के घटक को छोड़कर 1997-98 के बजट अनुमानों में 32,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह आश्वासन दिया है कि रक्षा संबंधी किसी भी अतिरिक्त पूंजीगत आवश्यकता के लिए वर्ष के दौरान पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा कर्मियों की शिकायतों के लिए अधिकरण

46. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्ष के दौरान सेवारत और सेवानिवृत रक्षा कर्मियों ने उच्च न्यायालय में कितनी याचिकायें दायर की हैं और उनमें से कितनी याचिकायें लम्बित हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार उन रक्षा कर्मियों की शिकायतों के समाधान हेतु एक न्यायाधिकरण की स्थापना करने का है जो सेवा नियम और संस्थानिक तथा हाउस रेमेडी सिस्टम के अन्तर्गत दायर किये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो यह न्यायाधिकरण कब तक गठित किया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू): (क) सेवारत तथा सेवानिवृत रक्षा कर्मिकों द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों में दायर की गई और लंबित पड़ी याचिकाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	सेवारत तथा सेवानिवृत्त रक्षा कर्मिको द्वारा उच्च न्यायालयों में दायर की गई याचिकाओं की संख्या	उच्च न्यायालयों में लंबित पड़ी याचिकाओं की संख्या
1992	727	213
1993	763	448
1994	1096	550
1995	1090	434
1996	1304	537

(ख) और (ग) सरकार ने सशस्त्र सेना कार्मिकों के लिए एक सशस्त्र सेना प्रशासनिक तथा कोर्ट मार्शल अधिकरण बनाया जाना सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया है। सरकार द्वारा अधिकरण स्थापित करने के लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं की गई है।

Defence production projects in Maharashtra

47. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have finalised a new policy for defence production in terms of emerging threat and technology advancement in the international scenario;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether a review of on-going defence production project has recently been undertaken and details thereof, particularly in respect of projects in Maharashtra;

(d) the details of the projects/proposals pending consideration/clearance by Union authorities and reasons for delay; and

(e) the details of fund allocation for defence production projects in Maharashtra during the current year for upgradation / modernisation / expansion / diversification etc. project-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) to (e) The content of Defence Production is sought to be concurrently related to emerging threats and dictates of technology. This is

achieved by development and productionisation of new hardware and upgradation of production technologies through renewal and replacement of existing plants.

On-going projects under the ordnance factories were recently reviewed. Projects for the production of 5.56 ammunition are under implementation in Maharashtra at the Ammunition Factory, Kirkee and Ordnance Factory, Varangon. These projects are expected to be fully commissioned during 1998-99. The allocation of funds during the current year for these projects is Rs. 34 crores.

No projects are pending clearance of the Government.

नेतरहाट फील्ड और खिजड़ी फायरिंग रेंज का निर्माण

48. श्री ज्ञान रंजन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज तथा खिजड़ी फील्ड फायरिंग रेंज बनाने का फैसला रक्षा मंत्रालय की सहमति से हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या लाखों आदिवासी, जो बेघर हो जाएंगे, की कठिनाई और परेशानियों का ध्यान रखा गया था;

(ग) क्या इन फील्ड फायरिंग रेंज के विरोध में जन-आन्दोलन हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का इन फील्ड फायरिंग रेंज के निर्माण की योजना को छोड़ देने का प्रस्ताव है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन० वी० एन० सोमू): (क) से (घ) नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को बिहार सरकार ने युद्धाभ्यास, फील्ड फायरिंग और तोपखाना अभ्यास अधिनियम, 1938 के अंतर्गत 1956 से अधिसूचित कर रखा है। समय-समय पर बढ़ाई गई यह अधिसूचना मई, 2002 तक वैध है। खिजडी फील्ड फायरिंग रेंज नहीं है।

विद्यमान अधिसूचित रेंज के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों को संघट्टन क्षेत्र तथा कैंपिंग ग्राउंड के रूप में अर्जित करने के प्रस्ताव को जनाक्रोश और बिहार सरकार के सुझावों के परिणामस्वरूप आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

Advantages of disadvantages of Sukhoi multirole aircraft

49. SHRI SOM PAL: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is correct that the Sukhoi multi-role aircraft acquired by the Indian Airforce is a modified version of the original Russian design;

(b) if so, the details indicating advantages and disadvantages thereof;

(c) whether it is also correct that there have been some criticism of the capability of the modified aircraft as well as the modalities of the agreement; and

(d) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU): (a) Yes, Sir. It is a modified and improved version of original SU-27 Trainer aircraft.

(b) Upgraded version of SU-30K to be procurred from Russia will be a state-of-the-art modern air superiority fighter capable of ground attack as well.

(c) and (d) No criticism of the capability of the modified aircraft being procured, as well modalities of the agreement, has come to the notice of the Government.

Closure of Women's Jail at Hosangabad

50. SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the reasons for closure of the Women's jail at Hosangabad (M.P.) inspite of the fact that various jail reform committees/commissions have recommended separate jails for women prisoners and the National